(b) the per capita per day milk consumption level set by the World Health Organisation; and

(c) the steps being taken to achieve the W.H.O. consumption level in India?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) As per 50th round of National Sample Survey (1993-94), per capita/ day consumption of milk works out about 134 gm. in rural areas and 149 gm. in urban areas as against the recommended dietary intake of 220 gm. of milk per capita per day.

(b) and (c) No norms have been set by the WHO. The norms recommended by the concerned country are acceptable to the WHO. In order to increase the production of milk and thereby to achieve the recommended consumption level, various Central Sector/ Centrally Sponsored Scheme are being implemented.

Scheme for cattle Insurance Cover

26. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a scheme for providing comprehensive cattle insurance cover, particularly in rural areas;

(b) if so, broad outlines of the scheme; and

(c) by when this scheme is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) and (c) A cattle insurance scheme is already being implemented by the General Insurance Corporation of India. However, to improve its coverage and scope a Task Force has been constituted by Government of India.

(b) The scheme covers death of animals/ cattle by accidents, diseases, fire, flood, strike and riot. The cattle includes milch cows and buffaloes, stud-bulls, bullocks, calves and heifers of specified age group.

गुजरात में लम्बित पड़ी डेयरी योजनाएं

27. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात दुग्ध योजना और राष्ट्रीय डेयरी निगम की अनेक योजनाएं भूमि की अनुपलब्धता के कारण लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का अहमदाबाद में वृहद् राष्ट्रीय डेयरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अहमदाबाद के निकट गांधीनगर में हाल ही में प्रतिदिन 10 लाख लीटर की क्षमता की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली एक मेगा डेयरी की स्थापना की गई है।

Increase in the prices of life saving drugs

28. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of life saving drugs manufactured in the country are very highly priced;

(b) whether Government have examined the World Health Organisation's suggestions made in 1985 and the Hathi Committee to provide life saving drugs at a cheaper rate;

(c) whether such drugs are decontrolled under the Modified Drug Prices (Control) Order, 1987;

(d) whether the prices of life saving drugs in respect of TB patients have gone up by 200% of the base price level of 1987; and

(e) if so, the details of such drugs and efforts made or being made by Government to make available the life saving drugs at cheaper rates?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) The Pharmaceutical Industry produces wide range of drugs and formulations in the country. The policy in regard to pricing aspects of drugs and formulations is a part of the Drug policy, 1986, which was modified in September, 1994 after having discussions at various levels including both the Houses of Parliament. This was followed by promulgation of Drugs (Prices Control) Order, 1995 on 6.1.95 and the drugs in whose cases prices are determined by the Government are in its First Schedule. The selection of these drugs is in accordance with the criteria laid down in the Modifications announced by the Government viz. drugs having a minimum annual turnover of Rs. 400 lakhs and having no competition and drugs having turnover less than Rs. 400 lakhs but more than Rs. 100 lakhs and having monopoly situation have been kept under price control.

(d) and (e) Most of commonly used anti-tuberculosis drugs were under price control during the contraversey of the Drugs (Prices Control) Order, 1987 and accordingly the prices for the commonly used anti-TB drugs were being regulated by the Government under the provisions of DPCO '87. Under DPCO '95 some of the drugs, viz. Ethambutol, Isoniazid, Sodium PAS, Thiacetazone etc. do not fall under price control as per criteria laid down. However Government is keeping a close watch on the prices of the formulations based on these drugs. If situation so warrants, Government would not hesitate to bring back these drugs under price control in public interest.

यूरिया खाद के प्रयोग से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव

29. **श्री रामबीलाल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरिया खाद्य के प्रयोग से कृषि योग्य जमीन खराब हो जाती है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार ने इसके स्थानापन्न का पता लगा लिया है, जिसका प्रयोग किसानों द्वारा किया जा सके और जो खर्चीली भी न हो, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यूरिया के प्रयोग से कृषि योग्य भूमि को नुकसान होता है। मूल्य एवं संचलन नियंत्रणाधीन यूरिया का कोई विकल्प नहीं है और इस प्रकार यह नाइट्रोजन का सस्ते से सस्ता स्रोत है। दूसरे रासायनिक उर्वरकों जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि का प्रयोग नाइट्रोजन के पूरकों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, सरकार एकीकृत पोषक आपूर्ति के लिए जैव खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद तथा जैव-उर्वरकों जैसे पोषकों के अन्य सस्ते स्रोत के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रही है।

उर्वरकों की कीमतों में संशोधन

30. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की कीमतों में संशोधन करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लिया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने अथवा कम करने जा रही है, यदि नहीं तो उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि करने का क्या औचित्य है, और

(ग) यदि उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होती है तो संशोधित कीमत क्या होगी तथा छोटे और मझौले किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां। सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन यूरिया के मूल्य में 21.2.1997 से 10% वृद्धि की गई है। फास्फेटिक, पोटाशिक तथा कम विश्लेषित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है।

(ख) फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत की दरों में भी 1.4.1997 से उपयुक्त वृद्धि की जा रही है। दोनों उपाय एनपी के पोषकों के उपयोग में असन्तुलन को कम करने की दृष्टि से किये गये हैं।

(ग) यूरिया का संशोधित मूल्य दिनांक 21.2.1997 से 3660/- रुपये प्रति टन है। यह छोटे तथा सीमान्त कृषकों सहित सभी श्रेणी के कृषकों के लिए लागू होगा।